हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

मारवाड़ का मित्र

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post Reg No. RJ/SRO/9657/2023-25

www.marwadkamitra.in twitter.com/MARWADKAMITRA facebook.com/marwarkamitra/ youtube.com/c/mkmnewsnetwork

वर्ष 22 | अंक 4 | सांचौर, गुरुवार, 15 फरवरी 2024 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव, | मूल्य वार्षिक 350 रुपये | कुल पृष्ठ - 4

कस्टम हायरिंग केन्द्र होंगे मोबाइल एप्प पर रजिस्टर्ड

जयपुर । प्रदेश की जीएसएस व केवीएसएस के माध्यम से संचालित कस्टम हायरिंग केन्द्र अब कृषि विभाग के राज किसान कस्टम हायरिंग केन्द्र एप्प पर रजिस्टर्ड होगे । इसके लिए कृषि आयुक्तालय के उप निदेशक कृषि (अभि.) राजीव आचार्य ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर को पत्र भेजकर निर्देशित किया हैं कि कस्टम हायरिंग केन्द्र को विभागीय पोर्टल राज किसान कस्टम हायरिंग केन्द्र एप्प पर रजिस्ट्रेशन किया जाए, ताकि कस्टम हायरिंग एप्प के माध्यम से किसानों को प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं की बुकिंग की जा सकें और एप्प के माध्यम से कृषक किराये पर ट्रेक्टर एवं यंत्र अपनी सुविधानुसार बुक करा कर सेवाएं प्राप्त कर सकें । इसके लिए कृषि आयुक्तालय ने सहकारिता विभाग से अधिकारी का नाम, अधिकारी का पदनाम, कार्यालय का नाम, मो. नम्बर और एसएसओ डी की जानकारी मांगी है।

आरबीआई के बोर्ड की हुई 606वीं बैठक

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 606वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भी उपस्थित थीं। श्रीमती सीतारामन ने अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रमुख क्षेत्रों और वित्तीय क्षेत्र से अपेक्षाओं पर प्रकाश डाला। बोर्ड ने भू-राजनीतिक विकास और वैश्विक वित्तीय बाजार की अस्थिरता से उत्पन्न चुनौतियों सहित वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति और दृष्टिकोण की भी समीक्षा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में डिप्टी गवर्नर डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे. और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशकों ने भाग लिया। बैठक में वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड और पंकज चौधरी, वित्त ा सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन और सचिव श्री तुहिन कांत पांडे और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे।

मारवाड़ का मित्र

हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

यदि आपको अपने क्षेत्र से लगाव है तो कृपया मारवाड़ का मित्र हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र के लिए मारवाड़ आंचल के विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक कला,संस्कृति आदि अन्य सामाजिक,शैक्षणिक, व्यवसायिक स्थलों पर लेख,कथा, कहानी विवरण आदि हमें अवश्य प्रकाशनार्थ भिजवाने । प्रकाशन सामग्री के साथ संबंधित स्थल का फोटो भी एवं आपका फोटो भी अवश्य भिजवाएं ।

-संपादक

पशुपालक क्रेडिट योजना धरातल पर नहीं उतरी थी, अब गोपाल क्रेडिट कार्ड

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । गत कांग्रेस सरकार द्वारा पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालक क्रेडिट योजना (पीसीसी) शुरू की थी, लेकिन बैंकों द्वारा खास रुचि नहीं लेने, पशुपालन विभाग को स्पष्ट गाइडलाइन ना होने व पशुपालकों को जानकारी के अभाव के कारण प्रदेश के पशुपालकों को इसका लाभ अब तक नहीं मिल पाया। अब उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बजट में पशुपालकों की आय में वृद्धि व आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड के तहत एक लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा की है। पशुओं के आवास, चारा, पशु आहार इत्यादि खरीदने व बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नोडल स्तर पर कमेटी का गठन कर पशु चिकित्सा उपकेंद्र तक मॉनिटरिंग की जाएगी। विस्तृत गाइडलाइन आते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

जिलेवार तय करेंगे लक्ष्य

मंत्री पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि पशुपालन के क्षेत्र में

राज्य को अग्रणी स्थान में लाने का पूरा प्रयास होगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड गांव-ढाणी में बैठे अंतिम पशुपालक तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए जिलेवार लक्ष्य तय कर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

ऐसे मिलेगा फायदा

पशुपालक को अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सा उपकेंद्र पर पर पंजीयन करवाना होगा जिसमें पशु का आधार (पशु के कान में 12 अंकों वाला पीला टैग) बनवाना होगा। कान में टैग लगने के बाद ही पशु का पंजीयन माना जाएगा। साथ ही पशुपालक का आधार कार्ड व बैंक डायरी की छाया प्रति जमा करवाई जाएगी। इसके बाद बैंक के माध्यम से अल्पकालीन ऋण दिया जाएगा।

गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से क्षेत्र में डेयरी उद्योग बढ़ने की संभावना

सांचौर जिले में नर्मदा नहर परियोजना से परंपरागत कृषि लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में किसानों को पशुपालन की ओर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अब राज्य सरकार के बजट में गोपालन हेतु गोपाल क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की गई है। इसके तहत गौ पालकों को एक लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध होने से क्षेत्र में किसान अपने यहां 1-2 गायों की गौशाला या डेयरी शुरू कर पाएंगे।

दुर्घटना बीमा योजना के तहत दिया 10 लाख रुपए का चेक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर । जिले की केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा बाटाडु अंतर्गत संचालित छीतर का पार ग्राम सेवा सहकारी समिति के ऋणी सदस्य भंवराराम जाट की दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहकारिता विभाग की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख का चेक नॉमिनी को सौंपा। बीमा क्लेम मृतक के आश्रित दावेदार मृतक भंवरलाल जाट की पत्नी श्रीमती अनसी देवी को शाखा प्रबंधक मोतीलाल सुथार, सहायक शाखा प्रबंधक सुशील तिवारी, ऋण पर्यवेक्षक शेराराम भाटिया के सानिध्य में सुपुर्द किया। ऋण पर्यवेक्षक शेराराम भाटिया ने बताया कि ऋणी सदस्य पुत्र पदमाराम जाट निवासी धतरवालों का सरा की वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना से मौत हो गई थी, मृतक का सहकारी समिति में सहकारिता विभाग की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा प्रीमियम कटा हुआ था, जिससे उन्हें इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का चेक दिया गया है। इस दौरान हरिराम शर्मा, रविन्द्र शर्मा, हेतराम सुथार, पूनमाराम गोदारा, परबत सिंह आदि उपस्थित रहें ।

पूर्वी जिलों की सिंचाई और पेयजल के लिए एकीकृत ईआरसीपी का त्रिपक्षीय समझौता किया

मानवता की सेवा में महती भूमिका निभा रहा मजदूर वर्ग सबके लिए राष्ट्र हित हो सर्वोपरि-शर्मा

संकल्प पत्र में किए हर एक वादे को पूरा करेगी राज्य सरकार

अब अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई स्थान नहीं-भजनलाल शर्मा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति मजदूर संघ का वैचारिक आधार है तथा यह वर्ग मानवता की सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सबके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए तथा इसी अवधारणा से विकसित भारत के संकल्प को पूरा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री आबू रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारी आश्रम शांतिवन में आयोजित भारतीय मजदूर संघ के 25वें प्रदेश अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के इस समय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छू रहा है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक श्री निंबाराम एवं भारतीय मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह डाबी सहित मजदूर संघ के केंद्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी मौजूद रहे।

भारतीय मजदूर संघ के 25वें प्रदेश अधिवेशन को संबोधित करते भजनलाल शर्मा

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार सिर्फ घोषणाएं ही नहीं करेगी बल्कि संकल्प पत्र में किए गए हर एक वादे को धरातल पर उतारेगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार ने प्रथम चरण में आंगनबाड़ी कर्मियों एवं पंचायत कर्मियों के मानदेय में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक हजार रुपए से बढ़ाकर 1 हजार 150 रुपए प्रतिमाह तथा 73 लाख गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेण्डर देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसा और पेपर लीक प्रकरणों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य में अपराध और संगठित अपराधों पर नियंत्रण के लिए हमारी सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है। अब अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। श्री शर्मा ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के जिलों की सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना (एकीकृत ईआरसीपी) का त्रिपक्षीय समझौता किया है। अब इस परियोजना को त्वरित गति से आगे बढ़ाया जा रहा है।

16 फरवरी को प्रधानमंत्री करेंगे वर्चुअल संवाद

जालोर। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 फरवरी को प्रातः 10 बजे विकसित भारत संकल्प अभियान को लेकर वर्चुअल संवाद करेंगे जिसमें जालोर जिले में विधानसभावार समारोहपूर्वक कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम को लेकर जिला कलक्टर निशान्त जैन की अध्यक्षता में जालोर जिले के उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों व विकास अधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला कलक्टर निशान्त जैन ने समारोह की रूपरेखा एवं पूर्व तैयारियों को लेकर जानकारी दी।

कर्मचारी भविष्य निधि पर अब 8.25 प्रतिशत ब्याज दर

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली । सेवानिवृत्ति निधि निकाय ने 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर तीन साल की उच्चतम ब्याज दर 8.25 प्रतिशत तय की। मार्च 2023 में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 2022-23 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को 2021-22 में 8.10 प्रतिशत से मामूली बढ़ाकर 8.15 प्रतिशत कर दिया था। एक सूत्र ने कहा कि ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) ने अपनी बैठक में 2023-24 के लिए ईपीएफ पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर प्रदान करने का फैसला किया है। 2020-21 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.5 प्रतिशत ब्याज दर सीबीटी द्वारा मार्च 2021 में तय की गई थी।

सहकार नेता ने सहकारिता में भ्रष्टाचार पर एक्शन में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति का किया स्वागत

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । सहकारी बैंको की आर्थिक सुदृढ़ता व मज़बूती को किसानों की समृद्धि व खुशहाली का पर्याय बताते हुए ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्पलाइज यूनियन के प्रान्तीय महासचिव एवं सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने सहकारी संस्थाओं में निरतंर उजागर हो रहे गबन व अनियमितताओं के मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक की सहकारिता में भ्रष्टाचार पर एक्शन में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति का स्वागत किया है। साथ ही, सहकार नेता ने भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के फिट एंड प्रॉपर मानदंडों के तहत केन्द्रीय सहकारी बैंक में प्रबंध निदेशक पद पर योग्य, बेदाग व ज़िम्मेदार अधिकारी लगाए जाने की मांग की है। वही, सीसीबी में एमडी व अधिशासी अधिकारी के पद पर स्वीकृत कैडर पर उसी पदनाम स्तर के अधिकारी लगाने की आवश्यकता बताते हुए श्री आमेरा ने कहा कि वर्तमान में 20 सीसीबी व अधिकांश प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक में फिट एंड प्रॉपर मानदंडों से योग्य, सक्षम एवं स्वीकृत कैडर के अधिकारी नहीं है, जिस पर नाबार्ड ने आपत्ति की हुई है। गृह जिलों की सहकारी बैकों सहित संभाग स्तर पर लंबे समय से एक ही जगह जमे अधिकारियों को राज्य स्तरीय सेवा के हिसाब से नियोजित किया जाए ।

जवाबदेही व ज़िम्मेदारी हो तय

सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने सहकारी संस्थाओं में निरतंर उजागर हो रहे गबन व अनियमितताओं के मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति, घाटे, एनपीए, गबन अनियमितता के लिए जवाबदेही व ज़िम्मेदारी तय कर एसीआर में दर्ज की जाए ।

एक्शन मोड में सहकारिता मंत्री दो अधिकारियों को किया सस्पेंड

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएम बनते ही प्रदेश की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी. ऐसे में अब सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने अपने विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना शुरू कर दिया है. इस बीच सहकारिता मंत्री गौतम कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. उन्होंने सहकारिता विभाग के दो अधिकारियों को सस्पेंड करने के साथ एक अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है. सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि हमारी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो प्रतिबद्धता है, उसको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने बयानों के माध्यम से सार्वजनिक किया है. हमारी सरकार के दो महीने के कार्यकाल में जिस प्रकार से वह काम कर रहे हैं, वह हम सबके सामने हैं. ऐसे में कोऑपरेटिव में भी जो भी शिकायतें आती हैं, उनकी जांच करवा कर जो भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है. हमने कुछ कार्रवाईयां भी की हैं. सहकारिता मंत्री कहा कि हम अभी एक्शन मोड में हैं.

लगातार खुल रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहां कि कोऑपरेटिव सोसाइटी लगातार खुल रही हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी खुलना कोई पाप नहीं है. अगर उसमें कोई अपराध होता है, तो वह भ्रष्टाचार और पाप है. उन अपराधों को लेकर हमारा सहकारिता विभाग सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित है. हमारे विभाग में मैंने पहले दिन से ही कहां है कि हमारी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है. गौतम कुमार ने कहा कि हम हमारे विभाग में भी कठोर कार्रवाई करेंगे. हमारे पास जो भी शिकायत आएगी, उस पर कठोर कार्रवाई करके दोषी को दंडित करने का काम भी हमारा विभाग करेगा. अगर किसी निवेशक का पैसा रुकता है, तो उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है और हम उस निवेशक का पैसा दिलवाने का काम भी करेंगे.

अब प्रतिभासिंह संभागीय आयुक्त, शक्तिसिंह सांचौर जिला कलक्टर

पाली . कार्मिक विभाग ने 33 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। इसमें पाली संभाग में भी फेरबदल किया गया है। पाली संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी को बीकानेर भेजा गया है। जबकि कोटा की संभागीय आयुक्त प्रतिभासिंह को पाली संभागीय आयुक्त लगाया है। राजफैड के प्रबंध निदेशक शक्तिसिंह राठौड़ को सांचौर कलक्टर लगाया है। वहीं, सांचौर कलक्टर पूजा कुमारी पार्थ का जालोर तबादला किया है। पूजा की बतौर कलक्टर यह दूसरी पोस्टिंग है। वहीं, राठौड़ को पहली बार जिले की कमान सौंपी गई है। जालोर कलक्टर निशांत जैन का तबादला बाड़मेर किया गया है।

किसानों का ईसबगोल की खेती की ओर बढ़ा रुझान

डेगाना । उपखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचल में इस बार किसानों ने ईसबगोल फसल की बंपर बुवाई की है। इन दिनों खेतों में चारों तरफ ईसबगोल की फसल लहलहा रही है। किसान देवाराम ठोलिया लवादर ने बताया कि यह ईसबगोल की फसल कम पानी में भी तैयार हो जाती है। इसलिए किसानों का रुझान बढ़ा है। आसपास के क्षेत्र में पानी की कमी है। बारिश के पानी या कम पानी से ईसबगोल की फसल तैयार होने के बाद किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यही कराण है कि खेतों में ईसबगोल लहलहा रही है।

कार्यवाहक के भरोसे चल रहा ऋण पर्यवेक्षक का कार्य

प्रकाश वैष्णव
Www.marwadkamitra.in

जालोर । *केन्द्रीय सहकारी बैंक में पांच साल बाद भी अधिशासी अधिकारी सहित 4 सहायक अधिशासी अधिकारी व 12 ऋण पर्यवेक्षक के पद रिक्त पड़े हैं। मात्र सीसीबी की संचालित विभिन्न शाखाओं में ग्राम सेवा सहकारी समितियों से व्यवस्थापकों के भरोसे सीसीबी की शाखा कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक के सहारे चल रही है। इन हालात में ऋण वितरण, ऋण वसूली से लेकर समितियों के निरीक्षण का प्रभावी संचालन भी नहीं हो रहा है।*

गौरतलब है कि 2018 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों में रिक्त ऋण पर्यवेक्षकों के पदों पर सेवानियम में व्यापक संशोधन के पश्चात आज दिन तक रिक्त पदों पर भर्ती सहकारिता विभाग नहीं करवा पाया हैं तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक में अधिशासी अधिकारी का पद पांच साल से रिक्त पड़ा है। विंडमना है कि सीसीबी की सांचौर व जालोर जिले में कुल 12 शाखाएं संचालित है । लेकिन इन शाखाओं में अभी तक स्थाई ऋण पर्यवेक्षक नहीं होने से शाखा क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक कों कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक बनाकर पदों को भरा गया हैं। जिसमें आहोर शाखा में तीन कार्यवाहक, सांचौर शाखा में दो, अरणाय शाखा में एक, धुम्बड़िया शाखा में एक, जालोर शाखा में दो, जसवंतपुरा शाखा में एक, रानीवाड़ा शाखा में एक, चितलवाना शाखा में दो, रामसीन शाखा में एक, मेंगलवा शाखा में एक व्यवस्थापक बतौर कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक कार्यरत है। अब तक कार्यवाहक के रूप में व्यवस्थापक लम्बे समय से कार्यरत है । लेकिन अभी तक स्थाई नियुक्ति नहीं होने से सीसीबी की शाखाओं के ऋण वितरण, ऋण वसूली का कामकाज प्रभावित हो रहा है। खास बात यह है कि सांचौर शाखा में सहायक अधिशासी अधिकारी का पद भी स्थाई तौर पर रिक्त पड़ा है। अभी तक अतिरिक्त चार्ज के तौर पर ही सहायक अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्य संपन्न करवाया जा रहा हैं ।

यह है स्वीकृत पदों पर स्थिति

अधिशासी अधिकारी एक पद रिक्त

सहायक अधिशासी अधिकारी चार पद रिक्त

ऋण पर्यवेक्षक के 12 पद पर कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक कार्यरत

एक्सपर्ट राय

केन्द्रीय सहकारी बैंक की विभिन्न शाखाओं में ऋण पर्यवेक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। कार्यवाहक व्यवस्थापक के पास बैंकिंग की ज्यादा जानकारी नहीं रहती है इसलिए लोग कामकाज को लेकर चक्कर निकालते रहते हैं। खासकर अधिशासी अधिकारी का पद रिक्त पड़ा है।

पैक्स कप्यूटराईजेशन में ईआरपी ट्रायल के लिए साप्ताहिक लक्ष्यों का हुआ आंवटन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालयकी ओर से देशभर की 60 हजार से ज्यादा प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां यानि पैक्स को कम्प्यूटराईजेशन के माध्यम से डिजीटल किया जा रहा है।

जिसके अंतर्गत प्रदेश की 5492 पैक्स को भी कंप्यूटराइज्ड किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें से 1260 पैक्स का ईआरपी ट्रायल रन पूर्ण होने के पश्चात प्रदेश की 4232 पैक्स ईआरपी ट्रायल रन से शेष होने पर, दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने एक आदेश जारी कर सीसीबीवार साप्ताहिक पैक्स ईआरपी ट्रायल रन करने के लक्ष्य आंवटित किए है।

अपेक्स बैंक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक में पैक्स कम्प्यूटराईजेशन योजना अन्तर्गत कार्य की धीमी गति को देखते हुए सहकारिता विभाग पंजीयक द्वारा साप्ताहिक आधार पर पैक्स ईआरपी ट्रायल रन के लक्ष्य दिये जाकर उक्त लक्ष्यों की समीक्षा कर प्रगति में आ रही समस्याओं से लगातार उच्च स्तर को अवगत करवाने के निर्देश दिए गए है।

संस्थापन व्यय तक का अभाव

प्रदेश की कई प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों में पिछले वर्षो से सहकारी बैंकों व सहकारी समितियों में के मध्य बढ़ते असंतुलन और ऋण माफी के पश्चात अल्पकालीन फसली ऋण वितरण में कटौती के चलते घटते ब्याज मार्जिन से सहकारी समितियों के संस्थापन व्यय तक का अभाव बना हुआ है। ओर-तो-ओर समितियों में स्टेशनरी खरीदने तक का बजट नहीं है। गौरतलब हैं कि सहकारी बैंकों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मध्य बढ़ते असंतुलन को नियत्रिंत करने के मामले में कोई बड़ा कदम उठाने की जगह जिमेदार केवल कमेटी गठन और पुर्नगठन पर जोर दे रहें है। वही, पिछले 4 माह पहले गठित कमेटी की दो बार बैठक आयोजित होने के बावजुद परिणाम शुन्य है।

नयी आवास योजना

शहरी क्षेत्र के गरीब तथा मध्य वर्ग आबादी के लिए प्रस्तावित आवास योजना की रूपरेखा बनाने तथा संभावित लाभार्थियों की योग्यता निर्धारित करने पर सरकार काम कर रही है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही घोषित किया है, इस योजना से किराये के घरों में, चॉल में और अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को फायदा मिलेगा. उल्लेखनीय है कि इस वर्ष दिसंबर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की अवधि समाप्त हो जायेगी. वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है, प्रस्तावित योजना वर्तमान में चल रही शहरी आवास योजना से अलग होगी. प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्तावित नयी योजना के बारे में पिछले वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में उल्लेख किया था. उस समय उन्होंने बताया था कि सरकार एक ऐसी आवास योजना लाने जा रही है, जिससे शहरी गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों को गृह ऋण में राहत मिलेगी. हालांकि नयी आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से अलग होगी, पर मौजूदा योजना में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूह के लोगों को मार्च 2022 तक ऋण संबद्ध अनुदान योजना के तहत कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता था. उस योजना में सरकार तीन से साढ़े छह प्रतिशत तक ब्याज अनुदान देकर 2.67 लाख रुपये तक का लाभ मुहैया कराती थी. बजट में प्रस्तावित आवास योजना की घोषणा सरकार के उस अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत सभी को आवास मुहैया कराने का संकल्प लिया गया है. इसी मिशन के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलायी जा रही है. शहरी आवास योजना के अंतर्गत 1.18 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अब तक 80 लाख घर तैयार हो चुके हैं. ग्रामीण आवास योजना में 2.94 करोड़ घर बनाना तय हुआ था, जिसमें नवंबर 2023 तक ढाई करोड़ घर बनाये जा चुके हैं. अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने बताया था कि ग्रामीण आवास योजना के तहत तीन करोड़ घर बनाने का लक्ष्य पूरा होने के करीब है तथा अगले पांच वर्षों में दो करोड़ घर और बनाये जायेंगे ताकि परिवारों की बढ़ती संख्या के कारण बढ़ रही मांग की पूर्ति की जा सके. अंतरिम बजट में आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 80,671 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया गया है. आबादी के बड़े हिस्से का सबसे बड़ा सपना अपना घर होना है. आवास योजना से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं. नयी योजना से इस संख्या में और भी बढ़ोतरी होगी.

खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की नई राहों के अन्वेषी थे स्वामीनाथन

-डॉ. अरुणा व्यास

एम.एस. स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक भर नहीं थे बल्कि कृषि चिंतन से जुड़े विरल व्यक्तित्व थे। यह उनके ही प्रयास थे कि अधिक उपज होने पर किसानों को उत्पादित फसल ओने-पोने दाम में बेचनी नहीं पड़े।

हरित क्रांति के जनक रहे एम. एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न की घोषणा महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमारे यहां कृषि क्षेत्र में परंपरागत सोच के दायरे को ही नहीं बदला, बल्कि कृषि से जुड़े चिंतन को उन्नत बीज और कृषि उपकरणों से समृद्ध करने की आधुनिक दृष्टि भी दी। यह स्वामीनाथन ही थे जिन्होंने सबसे पहले हमारे यहां उच्च उत्पादकता वाली फसलों के लिए प्रयास प्रारंभ किया। ऐसे दौर में जब देश अकाल की विभिषिका से जूझ रहा था, स्वामीनाथन ने चावल और गेहूं की उन्नत किस्मों के शोध पर ध्यान दिया। खेती के अंतर्गत भूमि की उर्वरा शक्ति को ध्यान में रखते हुए अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्मों, उर्वरकों के समुचित उपयोग और अधिक प्रभावी कृषि तकनीकों का संयोजन करते हुए उन्होंने देश में गेहूं के उत्पादन को दोगुना करने की पहल की। गेहूं ही नहीं चावल की खेती पर भी इस तरह के प्रयोग किए जिससे उत्पादन में वृद्धि हो। गेहूं के मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उन्होंने संकर बीज विकसित किए। उनके द्वारा की गई इस पहल से ही देश में खाद्यान्न की कमी दूर करने पर कार्य किया। इसी से भारत खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। भारत रत्न पुरस्कार नहीं है। यह वह सम्मान है जिसके तहत भारत को अपनी मौलिक दृष्टि, चिंतन और सोच के साथ अपनी विलक्षण प्रतिभा से सम्पन्न करने के लिए कार्य किया जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो स्वामीनाथन का देश को दिया योगदान अपूर्व है। उन्होंने देश को भारतीय खेती की जटिलताओं पर गहरा अध्ययन किया। सिंचाई साधनों के अभाव, भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता, जैविक उर्वरकों के उपयोग के बावजूद उत्पादन में कमी और फसलों के उत्पादन के एक ही ढर्रे पर चलते हुए खेती करने की प्रवृति से उत्पादन में कमी को समझते हुए इस तरह के शोध कार्य किए जिनसे देश में कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो। फसल की उपज और उसके उत्पादन की वास्तविक स्थिति के अध्ययन पश्चात उनकी यह स्थापना थी कि फसलों का विविधिकरण जरूरी है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने धान जिन क्षेत्रों में ज्यादा होता है, वहां के आंकड़े एकत्र किए। उनका अध्ययन किया और वैश्विक स्तर पर जो कुछ खेती में हो रहा है उसके जरिए इस तरह के बीज, उर्वरकों और कृषि उपकरणों के समन्वय से प्रयोग किए जिससे भारत जैसे भौगोलिक विषमता वाले देश में खेती लाभकारी हो। उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ें। उनके प्रयास रंग लाए और इस तरह देश में हरित क्रांति की शुरूआत हुई। पर यह आसान नहीं था, इसके लिए उन्होंने कृषि चिंतन के ऐसे मॉडल पर देशभर में कार्य करने की ओर लोगों को अग्रसर किया जिससे परम्परागत खेती की संस्कृति के संरक्षण के साथ कृषि में उतदन आधुनिकता की ओर देश अग्रसर हो। एम.एस. स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक भर नहीं थे बल्कि कृषि चिंतन से जुड़े विरल व्यक्तित्व थे। यह उनके ही प्रयास थे कि अधिक उपज होने पर किसानों को उत्पादित फसल ओने-पोने दाम में बेचनी नहीं पड़े। कृषि भंडारण के साथ विपणन की नवीनतम तकनीक के जरिए उन्होंने खेती को लाभकारी किए जाने पर जोर दिया। बल्कि कृषि में बड़े उद्यमियों के जुड़ाव के जरिए उन्होंने भारतीय खेती को वैश्विक बाजार प्रदान करने में भी महत्ती भूमिका निभाई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहते उन्होंने देश में राष्ट्रीय पादप, पशु और मछली आनुवंशिक ब्यूरो की स्थापना की। अनाज की उच्च उपज वाली फसलों के विकास के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया, उर्वरकों और किटनाशकों के समुचित प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने की मुहिम चलाई और जैव विविधता प्रबंधन के जरिए पारिस्थितिकी संतुलन के लिए भी महत्ती कार्य किया। नम्बे के दशक में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए चेन्नई में उन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउण्डेशन की स्थापना की।

इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिला केन्द्रित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया। स्वामीनाथन का भारतीय कृषि को यही बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने कृषि क्षेत्र में चिंतन की धारा बदली। देश को हरित क्रांति की सौगात दी और कृषि की उस संस्कृति को पुनर्नवा किया, जिससे भारतीय कृषि समृद्धि की राहों पर अग्रसर हो। ऐसा ही हुआ भी।

-डॉ. अरुणा व्यास
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

राज्य भर की सहकारी डेयरियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान है

सरस ब्रांड को राजस्थान के अलावा पड़ोसी राज्यों में भी लोकप्रिय बनाने बनेगी योजना

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

ग्रास रूट लेवल तक दुग्ध उत्पादकों को सहकारी डेयरियों से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे और अधिक से अधिक नई प्राथमिक दंग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सरस ब्रांड को न केवल राजस्थान बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी लोकप्रिय बनाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए।

जयपुर । पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राजस्थान राज्य की सहकारी डेयरियों में उत्पादित सरस दूध की गुणवत्ता ही इसकी पहचान है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नव गठित सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य भर की सहकारी डेयरियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान है और इसके लिए नई कल्याणकारी योजनाएं अमल में लाई जाएंगी। ग्रास रूट लेवल तक दुग्ध उत्पादकों को सहकारी डेयरियों से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में नई प्राथमिक दंग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरस ब्रांड को न केवल राजस्थान बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी लोकप्रिय बनाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए। मंत्री कुमावत सरस संकुल मुख्यालय में राज्य भर की सहकारी डेयरियों के निर्वाचित अध्यक्षों के साथ आयोजित परिचर्चा में डेयरी अधिकारियों और निर्वाचित अध्यक्षों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दूध और सरस ब्रांड के पशु आहार में किसी तरह की कोई मिलावट बरदाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए एक राज्यस्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर मिलावटखोरी को रोकने के लिए एक अभियान चलाया जाना चाहिए। प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों की समाजिक सुरक्षा और उने हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी तथा वर्तमान में चल रही सुरक्षा योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जिला दुग्ध संघों के निर्वाचित पदाधिकारीगण तथा डेयरी अधिकारियों में बेहतर समन्वय स्थापित किए जाने के प्रयास होने चाहिए ताकि इसका लाभ आम दंग्ध उत्पादकों को मिल सके। उन्होंने आसीडीएफ सहित सभी जिला दुग्ध संघों में मानव संसाधनों की कमी पर चिन्ता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 656 पदों पर तुरंत भर्ती किए जाने पर जोर दिया और शेष पदों के लिए एनडीडीबी की विशेषज्ञ सेवाएं लेने के निर्देश प्रदान किए। परिचर्चा के दौरान प्रदेशभर से आए जिला दुग्ध संघों से आए जिला दुग्ध संघों के निर्वाचित अध्यक्षों ने राज्य में डेयरी विकास के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। और व्यावहारिक समस्याओं की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

पशुपालन मंत्री ने दुग्ध उत्पादकों को बकाया भुगतान करने हेतु राज्य सरकार की ओर से देय राशि के तुरंत भुगतान सहित अन्य समस्याओं के अतिशीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। परिचर्चा में भाग लेते हुए पशुपालन एवं गोपालन के प्रमुख शासन सचिव श्री विकास सीताराम भाले ने कहा कि राज्य में डेयरी की अपार संभावनाएं हैं। और इन संभावनाओं को तलाशने में सहाकरी डेयरियों के निर्वाचित अध्यक्षगणों की महती भूमिका है। उन्होंने खुशी जाहिर की कि राजस्थान ने दुग्ध उत्पादन में देश भर में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। उन्होंन आश्वस्त किया कि राज्य सरकार दुग्ध उत्पादकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगी।

सात साल में दो हजार मोरों की हत्या, चालीस फीसदी घटी आबादी

नरेन्द्र शर्मा
Www.marwadkamitra.in

भीलवाड़ा. राज्य में गांवों की खुशहाली का प्रतीक एवं भीलवाड़ा जिले का शुभंकर राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान खतरे में है। राज्य में मोर की चालीस फीसदी आबादी घटी है। यह चिंताजनक है। पुलिस के आंकड़े बताते है कि महज सात साल में मोर की हत्या के दो हजार से अधिक मामले दर्ज हुए। इनमें पीपुल फॉर एनीमल्स संस्था ने 359 मुकदमे विभिन्न जिलों में दर्ज कराए। प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरुकता का माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार व वन विभाग ने वर्ष-2021 में वन्य जीव की 33 प्रमुख प्रजातियों को जिलों का शुभंकर घोषित किया था। इनमें राष्ट्रीय पक्षी मोर भीलवाड़ा जिले का शुभंकर घोषित है। पीपुल फॉर एनीमल्स संस्था ने हाल ही में अजमेर जिले के बांदनवाड़ा कस्बे के बगराई चरागाह में 50 से अधिक मोरों एवं बूंदी जिले के नैनवा तहसील के भांडेड़ा में बांसी कस्बे के निकट 5 मोरों की जहरीले दाने डाल हत्या की प्राथमिकी सम्बंधित पुलिस अधीक्षक को दी।

सजा व जुर्माने का प्रावधान ; पर्यावरण विद सत्यनारायण व्यास बताते है कि मोर की हत्या के जुर्म में सात साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन लचीले कानून के कारण आरोपी छूट रहे है।

मोर की आबादी भी राज्य में चालीस फीसदी घटी है। हाईकोर्ट के प्रतिवर्ष मोर गणना कल टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी से कराने के आदेश है, लेकिन इसकी पालना नहीं हो रही। सरकार ने वर्ष-2018 में मोर की आबादी के आंकडे अंतिम बार सार्वजनिक किए थे।

– बाबूलाल जाजू, प्रांतीय संयोजक, पीपुल फॉर एनीमल्स

आबादी बढ़ने व मोरों के ठिकाने आवासीय कॉलोनियों में त दील होने से भी मोर लुप्त हो रहे है। मोर के संरक्षण के लिए कार्ययोजना बना रखी है। –

गौरव गर्ग, मुख्य उपवन संरक्षक, भीलवाड़ा

पूर्वी राजस्थान का हो सकेगा कायापलट

ईआरसीपी में समिलित रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनैरा बैराज, मेजा बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र, ईसरदा बांध की भराव क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ इनका पुनरूद्धार किया जाएगा। इसके अलावा मानसून के समय पार्वती, कालीसिंध, मेज नदी में मानसुन के दौरान आने वाले जरूरत से ज्यादा बरसाती पानी को बनास, मोरेल, बाणगंगा और गंभीरी नदी तक लाने की योजना है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ईआरसीपी से पूर्वी राजस्थान की 11 नदियों को आपस में जोड़े जाने की योजना है।

- **राजस्थान में पांच लाख अस्सी हजार हेक्टेयर असिंचित भूमि पर सिंचाई सुविधा बढ़ सकेगी**
- **अब विवाद के समाप्त होने के साथ ही ईआरसीपी राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी नहर परियोजना बन गई है।**
- **करोड़ों लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।**

पूर्वी राजस्थान का भाग्य सवारने वाली बहुप्रतीक्षित पार्वती-कालीसिंध-चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल लिंक प्रोजेक्ट (पीकेसी-ईआरसीपी) पर राजस्थान, मध्यप्रदेश और केन्द्र सरकार के बीच समझौता हो गया है। इस समझौते को दोनों राज्यों के 26 जिलों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए स्वर्णिम सूर्योदय का दिन कहा जा रहा है। परियोजना के जरिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में पांच लाख अस्सी हजार हेक्टेयर असिंचित भूमि पर सिंचाई सुविधा बढ़ सकेगी और करोड़ों लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। पीकेसी के ईआरसीपी के साथ एकीकृत करने के केन्द्र सरकार के प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच जल बंटवारे को लेकर दो दशकों से चल रहा विवाद खत्म हो गया। अब विवाद के समाप्त होने के साथ ही ईआरसीपी राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी नहर परियोजना बन गई है। ईआरसीपी की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजक्ट रिर्पोट) 2017 में वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में बनी थी। इसके बाद 2018 में राजस्थान में सरकार बदल गई और परियोजना दलगत राजनीति का शिकार हो गई। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार चाहती थी कि केन्द्र सरकार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, जिससे प्रोजेक्ट पर होने वाले खर्च का 90 प्रतिशत खर्चा केन्द्र सरकार को वहन करना पड़े और राज्य पर मात्र 10 फीसदी खर्च का ही भार पड़े। नीति आयोग की 7वीं बैठक में भी मुख्यमंत्री गहलोत ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि भाजपा इस मामले में राजनीति कर रही है। इस संबंध में गहलोत ने केन्द्र सरकार और जल शक्ति मंत्रालय को डेढ दर्जन से अधिक पत्र लिखे।

गहलोत सरकार का तर्क था कि योजना की डीपीआर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा 2017 में बनाई गई थी, हम राष्ट्रीय परियोजना की सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। इसके बाद से ही यह योजना केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षण के लिए विचाराधीन थी। हालांकि, बाद में मुख्यमंत्री गहलोत राज्य के संसाधनों के जरिए इस योजना को पूरा करवाने की बात कर रहे थे। उनक कहना था कि केन्द्र ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे या न दे राज्य सरकार अपने संसाधनों से इस परियोजना को पूरा करेगी। केन्द्र सरकार के उपक्रम वेप्कॉस लिमिटेड की ओर से तैयार प्रोजेक्ट रिर्पोट में इस योजना पर तकरीबन 37, 247.12 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है और पूरी परियोजना को अगले 7 साल में पूरा किया जाने का लक्ष्य है। दरअसल, केन्द्र और राज्य सरकार के अलावा इस परियोजना में एक पेच मध्यप्रदेश सरकार का भी था।

ईआरसीपी पर मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय तक विवाद था।

राजस्थान सरकार 75 फीसदी पानी की मांग कर रही थी जबकि मध्यप्रदेश 50 फीसदी से अधिक पानी देने के लिए तैयार नहीं था। पिछले पांच साल में न तो दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर सहमति बन पाई और न ही केन्द्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया।

लेकिन अब राजस्थान और मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डब्बल इंजन की सरकार आते ही प्रोजेक्ट को न केवल राष्ट्रीय परियोजना में बल्कि प्राथमिकता लिंक के रूप में शामिल किया गया है।

ईआरसीपी के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों में 2.02 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई भूमि विकसित हो सकेगी। साथ ही इन जिलों में स्थित बांधों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। परियोजना में पेयजल के लिए 1723.5 एमसीएम (मिलियन घन मीटर) का भी प्रावधान किया गया है। परियोजना के पूर्ण होने के बाद राज्य की लगभग 40 प्रतिशत आबादी अर्थात 3 करोड़ लोगों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। ईआरसीपी में सम्मिलित रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनैरा बैराज, मेजा बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र, ईसरदा बांध की भराव क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ इनका पुनरूद्धार किया जाएगा।

इसके अलावा मानसून के समय पार्वती, कालीसिंध, मेज नदी में मानसुन के दौरान आने वाले जरूरत से ज्यादा बरसाती पानी को बनास, मोरेल, बाणगंगा और गंभीरी नदी तक लाने की योजना है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ईआरसीपी से पूर्वी राजस्थान की 11 नदियों को आपस में जोड़े जाने की योजना है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लागू होने से न केवल स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नदियों को जोड़ने का सपना साकार होगा बल्कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए बांध और बड़े तालाबों में पानी का संचय किया जाएगा। इसका एक बड़ा फायदा आसपास के क्षेत्र के भूमिगत जलस्तर को ऊपर उठाने में मिलेगा।

साथ ही इन 13 जिलों के अंदर आने वाले उद्योगों सहित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआरसी) द्वारा 286.4 एमसीएम पानी का उपयोग कर सकेंगे। इससे राज्य के भीतर औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से इंदिरा गांधी नहर ने पश्चिमी राजस्थान की तकदीर बदल दी।

डॉ. एन.के. सोमानी
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

किसानों को फसल खराबे के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार कटिबद्ध - कृषि मंत्री

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बीमा कंपनियों द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर लगभग 27.84 लाख कृषकों को लगभग 1.59 करोड़ पॉलिसियों का वितरण किया जाएगा।

जयपुर,। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने पंत कृषि भवन में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण कर रबी 2023-24 की 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषकों को समय पर बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी नही मिलने से खराबा होने पर फसल की जानकारी एवम किसानों को बीमा के प्रति जागरुक करने के लिए पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाकर पॉलिसियों का वितरण 2 फरवरी से 29 फरवरी तक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो किसान इन शिविरों में पॉलिसी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, वे अपनी फसल बीमा पॉलिसी संबंधित कृषि पर्यवेक्षक से प्राप्त कर सकेंगे। डॉ. मीणा ने कहा कि किसानों को ओलावृष्टि, चक्रवात और चक्रवाती वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान झेलना पड़ता है। इन आपदाओं से कृषकों को राहत प्रदान करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वरदान साबित हो रही है। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रचार-प्रसार और किसानों को समय पर बीमा क्लेम का भुगतान मिल जाने से इस योजना की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानो को इन विकट परिस्थितियों में नुकसान होने पर सरकार द्वारा सहायता मिलने से आर्थिक मजबूती मिलती है, जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर पाते हैं। पॉलिसी वितरण के दौरान किसान पाठशाला के माध्यम से योजनाओं का प्रचार-प्रसार सभी ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। बीमा कंपनियों द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर लगभग 27.8 4 लाख कृषकों को लगभग 1.59 करोड़ पॉलिसियों का वितरण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषकों को खरीफ फसल के लिए 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिये 5 प्रतिशत प्रीमियम अदा करना पड़ता है। फसल बीमा सभी श्रेणी के कृषकों के लिए खरीफ 2022 से स्वैच्छिक है, लेकिन ऋणी कृषकों को योजना से पृथक होने के लिए योजना से जुड़ने के अन्तिम तिथि से सात दिन पूर्व लिखित में आवेदन किया जाना आवश्यक है। कृषि मंत्री ने 100 दिवसीय कार्ययोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 100 दिवसीय कार्ययोजना का उद्देश्य प्रदेश के सभी किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित हो। इस कार्ययोजना में शामिल कार्यो पर गम्भीरता से बिना देरी किए काम करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत निधारित लक्ष्यों को शत प्रतिशत पुरा करें। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि बीज उत्पादन अधिक से अधिक राज्य स्तर पर ही किया जाये। डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कृषि योजनाओं के प्रचार-प्रसार को धरातलीय रूप देने के लिए कृषि विभाग द्वारा 'कृषि आपके द्वार' अभियान पूरे राज्य भर में चलाये जाने के निर्देश दिये, जिससे योजनाओं की जानकारी ग्रामीण स्तर तक प्रत्येक किसान को पहुंचाई जा सकेगी। बैठक में प्रमुख शासन सचिव श्री वैभव गालरिया, आयुक्त कृषि श्री कन्हैया लाल स्वामी, आयुक्त उद्यानिकी श्री लक्ष्मण सिंह कुड़ी, प्रबंध निदेशक आरएसएससी श्री जसवंत सिंह, संयुक्त सचिव कृषि श्री कैलाश नारायण मीणा, विभागीय अधिकारी और कृषक उपस्थित रहे।

विवरण फार्म - 4

देखिए नियम (8)

मारवाड़ का मित्र (पाक्षिक) का स्वामित्व संबंधी विवरण

1. प्रकाशक का स्थान - सांचौर-(जालौर) ,
2. प्रकाशन अवधि - पाक्षिक,
3. मुद्रक का नाम - प्रकाश वैष्णव
(क्या भारतीय हैं) हां,
पता ; 1. रामदेव शक्ति कप्यूटर्स प्रिन्टर्स सांचौर 343041 जिला-सांचौर 2. वैष्णव कप्यूटर्स प्रिन्टर्स परावा 343041 जिला-सांचौर
4. प्रकाशक का नाम - प्रकाश वैष्णव
(क्या भारतीय हैं) ; हां,
पता ; सुभाष नगर सांचौर,
343041 जिला-जालौर
5. संपादक का नाम - प्रकाश वैष्णव
(क्या भारतीय हैं) ; हां,
पता ; सुभाष नगर सांचौर,
343041 जिला-जालौर
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार - प्रकाश वैष्णव, मालिक, अन्य कोई हिस्सेदार - नहीं

मैं प्रकाश वैष्णव एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य है ।

दिनांक 15 फरवरी 2023 — प्रकाश वैष्णव, प्रकाशक के हस्ताक्षर

पंचायतीराज उपचुनाव के लिए संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार सहिता लागू

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह फरवरी-मार्च 2024 के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रिक्त पदों वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जो चुनाव समाप्ति तक लागू रहेगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) शिवचरण मीना ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह फरवरी-मार्च 2024 के लिए घोषित किये गये कार्यक्रम के तहत जालोर जिले में आहोर पंचायत समिति की भोरडा ग्राम पंचायत में उप सरपंच तथा जालोर पंचायत समिति की आकोली ग्रा.पं. के वार्ड सं. 10 एवं आहोर पंचायत समिति की भोरड़ा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 11, निम्बला ग्रा. पं. के वार्ड सं. 11, अजीतपुरा ग्रा. पं. के वार्ड सं.1, चरली ग्रा.पं. के वार्ड सं. 3 व 1, बाला ग्रा.पं. के वार्ड सं. 5, वाकली ग्रा.पं. के वार्ड सं. 6, उम्मेदपुर ग्रा.पं. के वार्ड सं. 14, भैंसवाड़ा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 8 व बांकली ग्रा.पं. के वार्ड सं. 12, जसवंतपुरा पं.स. की तवाब ग्रा.पं. के वार्ड सं. 6 तथा बागोड़ा पंचायत समिति की राह ग्रा.पं. के वार्ड सं. 3 में वार्ड पंच के उप चुनाव करवाये जायेंगे।

चुनाव कार्यक्रमानुसार जालोर पंचायत समिति की आकोली ग्रा. पं. के वार्ड सं. 10, आहोर पंचायत समिति की भोरड़ा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 11, निम्बला ग्रा.पं. के वार्ड सं. 11, अजीतपुरा ग्रा.पं. के वार्ड सं.1, चरली ग्रा.पं. के वार्ड सं. 3 व 1, बाला ग्रा.पं. के वार्ड सं. 5, वाकली ग्रा.पं. के वार्ड सं. 6, उम्मेदपुर ग्रा. पं. के वार्ड सं. 14, भैंसवाड़ा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 8 व बांकली ग्रा.पं. के वार्ड सं. 12, जसवंतपुरा पं.स. की तवाब ग्रा.पं. के वार्ड सं. 6 तथा बागोड़ा पंचायत समिति की राह ग्रा. पं. के वार्ड सं. 3 में वार्ड पंच के रिक्त पदों पर उप चुनाव करवाये जायेंगे

जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अंतर्गत 15 फरवरी को निर्वाचन की लोकसूचना जारी की जायेगी तथा 20 फरवरी, 2024 (मंगलवार) को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

21 फरवरी, 2024 (बुधवार) को प्रातः 10 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी तथा अपरान्ह 3 बजे तक नाम वापिस लिये जा सकेंगे। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

1 मार्च, 2024 को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान करवाया जायेगा तथा मतदान समाप्ति के पश्चात् पंचायत मुख्यालय पर मतगणना करवाई जायेगी। इसी प्रकार जिले में आहोर पंचायत समिति की भोरड़ा ग्राम पंचायत में रिक्त उप सरपंच के पद पर उप चुनाव के लिए 2 मार्च, शनिवार को प्रातः 9 बजे से पूर्व बैठक के लिए नोटिस जारी किया जायेगा तथा प्रातः 10 बजे बैठक प्रारम्भ की जायेगी। पूर्वान्ह 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्र/प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण का समय रहेगा।

पूर्वान्ह 11.30 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी। पूर्वान्ह 11.30 बजे से अपरान्ह 12 बजे तक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जायेगा। अपरान्ह 12 बजे से 1 बजे यदि आवश्यक हुआ तो मतदान करवाया जायेगा तथा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् मतगणना एवं परिणाम की घोषणा की जायेगी।

जनसुनवाई में प्राप्त परिवादों पर करें त्वरित कार्यवाही

बाड़मेर,। जिले में आमजन की परिवेदनाओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण के लिए राज्य सरकार की त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत जिले के सभी उपखण्ड मुयालयों पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान शिव उपखण्ड मुयालय पर पंचायत समिति में जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजित की गई। इस दौरान उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई में विभिन्न मुद्दों से जुड़ें प्राप्त हुए प्रकरणों को जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को उक्त प्रकरणों का मौके पर जाकर जांच कर त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

इस मौके पर जिला कलेक्टर पुरोहित ने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए अगली सुनवाई से पूर्व निपटाएं जाए। उन्होनें कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित समाधान हेतु त्रिस्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था प्रारभ की गई है, जिसे गभीरता से लेते हुए उपखण्ड स्तरीय अधिकारी जनसुनवाई का प्रभावी पर्यवेक्षण करें। उन्होने कहा कि उपखण्ड स्तर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच करवाकर उपखण्ड स्तर से समाधान योग्य समस्याओं का वहीं निस्तारण करें ताकि परिवादियों को जिला मुयालय तक नहीं आना पड़े।

ब्याज में बदलाव को लेकर होगा फैसला

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की घोषणा करेगा। इस घोषणा पर वित्तीय बाजार सहभागियों की नजर रहेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के बयान के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शुरू हुई तीन दिवसीय द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक पर वित्तीय बाजार सहभागियों की पैनी नजर है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि खुदरा महंगाई के बावजूद आरबीआई रेपो रेट को पहले की तरह रखते हुए उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो मकान और गाड़ी की बिक्र ी में तेजी जारी रहेगी, क्योंकि मौजूदा ब्याज दरों पर मकान की खरीदारी में ग्राहक खुद को सहज महसूस कर रहे हैं। तभी चालू वित्त वर्ष में लिए जाने वाले खुदरा लोन में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी हाउसिंग लोन की है। चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई दर 5.5 प्रतिशत तक रह सकती है गाड़ियों की बिक्री भी लगातार बढ़ रही है और माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन में मकान और गाड़ी खरीदारी में और तेजी आएगी। मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक के बाद शुक्रवार को आरबीआई दरों की घोषणा करेगा। अगस्त में भी आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए उसे 6.5 प्रतिशत पर कायम रखा था। चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई दर 5.5 प्रतिशत तक रह सकती है। अगस्त की खुदरा महंगाई 6.8 प्रतिशत थी। सितंबर में इसमें कमी की संभावना है।

खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण कम हुई मुद्रास्फीति

तीन महीने के निचले स्तर पर महंगाई

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली ; आर्थिक मोर्चे पर आज देश के लिए राहत की खबर सामने आई है। आज जारी सरकारी आंकड़ो के मुताबिक देश में महंगाई अपने तीन महीने के नीचले स्तर पर पहुंच गई है। यह कमी मुख्य रुप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण आई है। सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.02 प्रतिशत पर आ गई है। आपको बता दें कि सितंबर में रिटेल मुद्रास्फीति आरबीआई ने अनुमान के स्तर 6 प्रतिशत से नीचे आ गई है। इससे पहले मुद्रास्फिति जुलाई में 7.4 प्रतिशत और अगस्त में 6.8 प्रतिशत थी। इससे पहले जून के महीने में महंगाई में कमी देखी गई थी जब खुदरा मुद्रास्फीति 4.87 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर पिछले महीने के 9.94 फीसदी से घटकर 6.56 फीसदी पर आ गई है। आर्थिक जानकारों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर लगातार कुछ महीनों तक पांच प्रतिशत के आसपास रहती है तो आरबीआइ भविष्य में ब्याज दरों में राहत देने पर भी विचार कर सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में खाद्य तेल व वनस्पति के खुदरा दाम में पिछले साल सितंबर की तुलना में 14.04 प्रतिशत की गिरावट आई। वहीं, दाल व दलहन के दाम में 16.38 प्रतिशत, अनाज के दाम में 10.95 प्रतिशत तो मसाले के दाम में 23.06 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में महंगाई दर तीन महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह गिरावट मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की गिरती कीमतों के कारण है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर 5.02 फीसदी पर आ गई है जो आरबीआई के 6 फीसदी के अनुमान से कम है। पिछले दो महीने से महंगाई 6 प्रतिशत से उपर बनी हुई थी।

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

आहोर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी में अध्यक्ष पद पर श्रीमान् सूर्यवीरसिंह राठौड़ निम्बला एव उपाध्यक्ष पद पर श्रीमति लक्ष्मी कंवर भूति एवं संचालक बोर्ड सदस्य के तौर पर महेन्द्रसिंह शेखावत, अमरसिंह जोधा, खुशबु कुमारी, गणपतसिंह, प्रेमसिंह, श्रीमति गुलाब कंवर, श्रीमति चांद कंवर के निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

श्रीमान् सूर्यवीरसिंह राठौड़

श्रीमति लक्ष्मी कंवर

शुभेच्छु

तेजसिंह राजपुरोहित — व्यवस्थापक सेलड़ी जीएसएस
सुरेश कुमार चौधरी — व्यवस्थापक भूति जीएसएस
आशाराम चौधरी — व्यवस्थापक पादरली जीएसएस
नरपत खान शेख — व्यवस्थापक कांबा जीएसएस
भैरुसिंह कुपावत — व्यवस्थापक भोरड़ा जीएसएस
सवाराम मेघवाल — व्यवस्थापक कवराड़ा जीएसएस

अजीतसिंह मंडलावत — व्यवस्थापक सराणा जीएसएस
दीपाराम देवासी — व्यवस्थापक शंखवाली जीएसएस
दिनेश कुमार प्रजापत — व्यवस्थापक चूण्डा जीएसएस
भंवरु खान शेख — व्यवस्थापक बावड़ी जीएसएस
विनोदसिंह राजपुरोहित — व्यवस्थापक सुगालिया जोधा जीएसएस
कपूराराम चौधरी — व्यवस्थापक घाणा जीएसएस
आदाराम लुकड़ा — व्यवस्थापक रामा जीएसएस

मालाराम मेघवाल — व्यवस्थापक निंबला जीएसएस
प्रहलादसिंह जोधा — व्यवस्थापक भाद्राजून जीएसएस
छगनाराम मेघवाल — व्यवस्थापक वेडिया जीएसएस
नारायणलाल मीणा — व्यवस्थापक बिठुड़ा जीएसएस
लक्ष्मणसिंह राजपुरोहित — व्यवस्थापक मालगढ़ जीएसएस
राजीव मीणा — व्यवस्थापक रायथल जीएसएस
तालीम खान शेख — व्यवस्थापक अजीतपुरा जीएसएस

- सौजन्य - राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ ब्लॉक इकाई आहोर, जिला-जालोर

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है ।
अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 350/- ☐ दो वर्ष रु. 700/- ☐ तीन वर्ष रु. 1050/- ☐ छह वर्ष रु. 2100/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम..........
ग्राम.......... पोस्ट..........
तहसील.......... जिला..........
फोन.......... पिन कोड..........
राशि (रुपए) .... बैंक का नाम..........

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details :
Name: Marwad ka Mitra
A/C No.: 11134027554
IFSC Code: RMGB0000134
Google / Phonepay
9602473302

सदस्यता हेतु लिखें → मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र
संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा,
तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041
Mo. 9602473302, Visit Us:Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र

हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

सांचौर, गुरुवार, 15 फरवरी 2024

4

RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136

Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

किराये के भवन में चल रहा सहकारिता विभाग का उप रजिस्ट्रार कार्यालय

सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार कार्यालय के पास नहीं हैं अपना भवन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिला मुख्यालय पर सहकारिता विभाग का उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां एवं रजिस्ट्रार (संस्थाऐं) कार्यालय किराये के पुराने मकान में संचालित हो रहा है। इस कार्यालय के अधीन जिले में कार्यरत सहकारी संस्थाओं से संबंधित रिकॉर्ड संधारित रहता है। यहां, सहकारी संस्थाओं से लेकर सामाजिक संस्थाओं से संबंधित कार्य के लिए जिलेभर के आमजन की आवाजाही रहती है। किराये का मकान पुराना होने के चलते इसकी दीवारों में दरारें आने लग गई है। वहीं, बरसात के मौसम में छत टपकने की आंशका भी रहती है। इससे कार्यालय में संधारित रिकॉर्ड भीग कर खराब होने का अंदेशा कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों में रहता है।

आखिर कब बनेगा सहकार भवन ?

उप रजिस्ट्रार कार्यालय ही नहीं, अपितु विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां कार्यालय भी किराये के मकान में संचालित है। जिला मुख्यालय पर सहकार भवन नहीं होने से सहकारिता विभाग के इन कार्यालयों का संचालन अलग-अलग जगहों पर हो रहा है। जबकि, कई जिलों में सहकार भवन में सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय एक ही छत के नीचे संचालित हो रहें है।

सहकार भवन के लिए जमीन तक नहीं

जालोर जिला मुख्यालय पर सहकार भवन बनाने की पहल न तो जनप्रतिनिधियों ने की है, और न ही, उच्च अधिकारियों ने की है। वही, जिला मुख्यालय पर सहकार भवन बनाने की बात तो दूर, जिला मुख्यालय जालोर पर सहकार भवन के नाम से जमीन तक आंवटित नहीं है।

सूर्यवीरसिंह राठौड़ बनें आहोर को ऑपरेटिव मार्केटिंग के अध्यक्ष

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिले की आहोर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी मे राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की ओर जारी आदेश की पालना मे निर्वाचन अधिकारी श्रवण कुमार प्रजापत ने मतों की गणना के पश्चात मार्केटिंग के अध्यक्ष पद पर सूर्यवीरसिंह राठौड़ निम्बला एवं उपाध्यक्ष पद पर श्रीमति लक्ष्मी कंवर भूति निर्वाचित घोषित किया गया आहोर केवीएसएस में चुनाव प्रक्रिया 12 अप्रैल को ही संपन्न हो गई थी, लेकिन जोधपुर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के परिणाम को रोक दिया गया था, अब 18 जनवरी को हाईकोर्ट द्वारा रिट पिटिशन खारिज करने के बाद आज पदाधिकारियों के परिणाम की घोषणा की गई है। इस दौरान आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित, आहोर तहसीलदार हितेश कुमार त्रिवेदी, मार्केटिंग के मैनेजर सुरेश कुमार सारस्वत, लेखापाल पूरणसिंह, संचालक बोर्ड सदस्य महेन्द्रसिंह शेखावत (सेवानिवृत्त आर.सी.एस) अमरसिंह, खुश्बु कुमारी, गणपतसिंह, प्रेमसिंह, गुलाब कंवर, चांद कंवर एवं समिति कार्मिक रघुवीरसिंह, भंवरसिंह, विकास ओझा, लोकेश रामावत, फुलाराम मीणा आदि मौजूद रहें ।

नया राजस्थान और विकसित भारत बनाने के लिए आएं साथ- डॉ. प्रेम चन्द बैरवा

सहकारिता आन्दोलन है गांवो में राहत का आधार

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । अरांई में अजमेर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के उद्घाटन के अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा ने कहा कि नए राजस्थान और विकसित भारत बनाने के लिए सभी साथ आएं। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों को ऋण उपलब्ध करवाकर उनका जीवन स्तर उन्नत बनाया जाएगा। इस शाखा से क्षेत्र के निवासियों को लाभ होगा। नया राजस्थान बनाने के लिए सभी साथ आएं। राजस्थान की जनता का सहयोग राजस्थान के विकास को नई ऊचाईयों तक पहूंचाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित देश बनाने के लिए दिन-रात प्रयासरत है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाना होगा। सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचा रही है ।उन्होंने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए नदियों को जोड़ने का सपना देखा था। उसे सरकार वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भागीरथ प्रयास से पूर्ण कर रही है। जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह, मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के प्रयासों से यह कार्य आरम्भ हुआ। राज्य के जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने समस्त विभागीय कार्य तत्परता से करवाए। इसका सुखद परिणाम जल्द ही सभी के सामने होगा। प्रो. सांवर लाल जाट ने सरकार में मंत्री रहते हुए क्षेत्रा के विकास में काफी कार्य किया था। इस कार्य को वर्तमान सरकार आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। इस अवसर पर जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित, पुलिस अधीक्षक श्री चूनाराम जाट सहित जन प्रतिनिधि, समिति के सदस्य एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता आन्दोलन ग्रामीणों को राहत प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। यह किसानों के साथ हर समय खड़ा रहा है। सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि को 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार किया है।

उच्च न्यायालय द्वारा 682 प्रकरण आयोग के पक्ष में निस्तारित

जयपुर, । राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के हितों के दृष्टिगत् न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण कराने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2024 तक की अवधि में उच्च न्यायालय द्वारा 682 प्रकरणों का निस्तारण आयोग के पक्ष में किया है। इस अवधि के दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 9 प्रकरण, उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ द्वारा 251 प्रकरण, तथा उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा 422 प्रकरण, आयोग के पक्ष में निस्तारित किए गए हैं।

हिन्दी पाक्षिक
मारवाड़ का मित्र
विज्ञापन एवं समाचारों के लिए संपर्क करें
Website
Www.Marwadkamitra.in
Mo. 9602473302, 7976323829
Mail ID - marwadkamitra@gmail.com

राशन की दुकानों पर तौल में नहीं होगा झोल, नहीं कर सकेंगे गड़बड़ी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

पाली. राशन की दुकानों (उचित मूल्य की दुकानों) पर राशन डीलर अब किसी तरह से तौल में गडबड़ी नहीं कर सकेंगे। राशन की दुकानों पर वितरित किए जाने वाले राशन के लिए पॉस मशीनों को ई-तराजू से लिंक करने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिले की 757 राशन की दुकानों में से 100 दुकानों पर यह ई-तराजू पहुंच चुके हैं। पॉस मशीनों से ई-तराजू को लिंक करने के बाद राशन उपभोक्ता के अंगूठा लगाते ही राशन कार्ड की यूनिट संख्या स्कैन होगी। उसी के आधार पर राशन का तौल होगा। खास बात यह है कि इस तकनीक में एक कार्ड के तौल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दूसरा कार्ड सक्रिय होगा। डीलर इस तकनीक में छेड़छाड़ का प्रयास करेंगे तो वे तुरन्त पकड़ में आ जाएंगे। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी।

सहकारी भर्ती बोर्ड से भर्ती का प्रावधान फिर भी हो गई व्यवस्थापकों की नियुक्ति

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

***बाड़मेर ।** केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा सेड़वा अंतर्गत संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मनमाफिक कागजी कार्यवाही में समिति संचालक बोर्ड द्वारा नीतिगत निर्णय पारित के संबंध में एजेंडे जारी किए बगेर ही, परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए अयोग्ताधारी लोगो को समितियों में व्यवस्थापक पद का कार्यभार सौंपने के लिए समिति स्तर से प्रस्ताव पारित करने का, मामला सामने आया है। वही, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बाड़मेर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 2005 के पश्चात उप रजिस्ट्रार कार्यालय स्तर से जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सेल्समैन, सहायक व्यवस्थापक रखने संबंधी किसी प्रस्ताव का प्रमाणिकरण नहीं किए जाने की जानकारी दी गई है। हालांकि, सेड़वा शाखा क्षेत्र की सारला, बुरान का तला, सावा, हरपालिया, गुल्ले की बेरी, पनोरिया ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक पद पर नई नियुक्ति हो गई है। जबकि सहकारिता विभाग के पंजीयक कार्यालय द्वारा 3 अगस्त 2018 को एक पत्र उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां और सीसीबी प्रबंध निदेशक समस्त को जारी कर अवगत कराया गया था कि सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 यथा संशोधित 2016 की धारा 29 (ख) के तहत राज्य की सहकारी समितियों में कर्मचारियों के चयन और भर्ती की सिफारिश हेतु सहकारी भर्ती बोर्ड का गठन होने के पश्चात, किसी भी समिति की अध्यपेक्षा और आवश्यकता अनुसार चयन के मापदण्ड की प्रक्रिया एवं अभ्यर्थी के चयन की सूची तैयार करने बाबत् विनिश्चय करने की शक्ति सहकारी भर्ती बोर्ड में निहित होने के साथ ही, जारी पत्र के मुताबिक, 10 जुलाई 2017 को इस संबंध में जारी अधिसूचना के पश्चात सहकारी भर्ती बोर्ड के अतिरिक्त किसी भी स्तर पर संपादित की गई नियुक्ति की कार्यवाही विधि विरुद्ध और अमान्य है।*

यह है नियुक्ति की प्रक्रिया

समिति में कोई व्यवस्थापक या सहायक व्यवस्थापक की नियुक्ति करनी है तो समिति जिला मुख्यालय पर इसकी सूचना देगी और विभाग निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार 21 से 33 वर्ष आयु और बीए तक शिक्षित अभ्यर्थी को परीक्षा में पास होने पर नियुक्ति देगी।

इस बार धोरों में होगा पानी का बंटवारा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर. भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) की बैठक इस बार चंडीगढ़ की बजाय जैसलमेर में होगी। इसकी तैयारियों में जल संसाधन विभाग के अधिकारी जुट गए हैं। 16 फरवरी को धोरों के बीच होने वाली इस अहम बैठक में मार्च के शेयर का निर्धारण किया जाएगा। पानी के बंटवारे को लेकर हो रही उक्त बैठक में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के अधिकारी शामिल होंगे। राजस्थान का प्रतिनिधित्व जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता अमरजीत सिंह मेहरड़ा करेंगे। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार राजस्थान में बैठक होने से प्रदेश को आंशिक रूप से फायदा मिल सकता है। हालांकि शेयर का निर्धारण बांधों के जल स्तर के हिसाब से किया जाएगा। गत महीने के मुकाबले इस महीने पानी की आवक में कुछ सुधार भी हुआ है। इससे मार्च के शेयर में कुछ सुधार होने की उम्मीद है। वर्तमान में इंदिरागांधी नहर को तीन में एक समूह में चलाया जा रहा है। किसान इस नहर को चार में दो समूह में चलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन शेयर में कमी होने के चलते नहर को किसानों की मांग के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। मार्च में गेहूं की पकाई के लिए पूरा पानी देने की मांग किसान लंबे समय से कर रहे हैं। इस बैठक के संपन्न होने के बाद ही पता चल पाएगा कि मार्च में कितना पानी नहरों में चलेगा। इंदिरागांधी नहर से राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू सहित प्रदेश के बारह जिलों को जलापूर्ति हो रही है। इससे करीब तीन करोड़ लोगों की प्यास बुझ रही है। लाखों बीघा भूमि सिंचित हो रही है। इस स्थिति में प्रदेश के इन जिलों में नहरी पानी की काफी अहमियत रहती है।

बैठक के संपन्न होने के बाद ही पता चल पाएगा कि मार्च में कितना पानी नहरों में चलेगा।

आरबीआई ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऑनलाइन माध्यम से ऋण देने के संबंध में चेतावनी दी

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-एनबीएफसी को पीयर-टू-पीयर यानी ऑनलाइन माध्यम से ऋण देने के बारे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक को दिशानिर्देशों के अनुरूप कुछ अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं का पता चला है। श्री राव ने आज मुंबई में भारतीय उद्योग परिसंघ के एनबीएफसी शिखर सम्मेलन के छठे संस्करण को संबोधित किया। श्री राव ने कहा कि ऋणदाताओं का लाइसेंसिंग शर्तों और नियामक दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन अस्वीकार्य है। उन्होंने ऊंची ब्याज दरें वसूलने के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के प्रति रिजर्व बैंक की नाराजगी पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बैंक ऐसी प्रथाओं से परिचित है। डिप्टी गवर्नर ने कहा कि एनबीएफसी सेक्टर भारतीय वित्तीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हितधारक है। श्री राव ने आशा व्यक्त की कि एनबीएफसी आगे चलकर भारत के पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

सदस्यों में 11 लाख 62 हजार का लाभांश बंटेगा

बिलाड़ा बृहत बहुधंधी सहकारी संस्था का 63वां द्विवार्षिक अधिवेशन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बिलाड़ा सस्ते दामों पर किसानों को खाद, बीज ,ऊर्वरक एवं बिना ब्याज पर डेढ़ लाख रुपए तक की राशि का ऋण उपलब्ध करवाने वाली बिलाड़ा बृहत बहुधन्धी सहकारी समिति के 63वें वार्षिक अधिवेशन को संबोधित कर रहे विधायक अर्जुनलाल गर्ग ने समिति सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि किसी को अगर सहकारिता को सार्थक होते देखना है तो उन्हें यहां आना होगा। संस्था के अध्यक्ष लक्ष्मणराम लखावत ने द्विवार्षिक अधिवेशन के दौरान मौजूद सदस्यों को बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए कारोबार से सकल लाभ के रूप में 42 लाख 08 हजार रुपएअर्जित किए। शुद्ध लाभ के रूप में 8 लाख 30 हजार रूपये की राशि अर्जित की। इसमें से 5 लाख 84 हजार रुपए लाभांश के रूप में तथा वर्ष 2022-23 के दौरान संस्था ने 42 करोड़ 24 हजार रुपए का कारोबार किया। सकल लाभ के रूप में 57 लाख 80 हजार की राशि अर्जित की तथा इस राशि का विभिन्न मदों में समायोजन करने के पश्चात शुद्ध लाभ के रूप में 8 लाख 54 हजार रुपए अर्जित किया। इस राशि में से संस्था सदस्यों में लाभांश के रूप में पांच लाख 78 हजार रुपए बंटेंगे।

जल ही जीवन हैं
बूंद-बूंद बचाएं

भजनलाल शर्मा से राजस्थान के महाधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ताओं ने की शिष्टाचार भेंट

***जयपुर, ।** मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से राज्य के महाधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद ने मंगलवार शाम को ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। महाधिवक्ता ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री श्री शर्मा का अभिवादन किया। इस दौरान राज्य के नवनियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री गुरूचरण सिंह गिल, श्री भरत व्यास, श्री बसंत सिंह छाबा, श्री भुवनेश शर्मा एवं श्री सुरेन्द्र सिंह नरूका भी उपस्थित रहे।*

बारदाना का अभाव बताकर रोकी खरीद

समर्थन मूल्य पर सात दिन बाद ही अटकी खरीद, किसान परेशान

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर । गत छह फरवरी को फलोदी कृषि उपज मंडी व आऊ उपखण्ड मुख्यालय पर समर्थन मूल्य पर शुरू हुई मूंगफली की खरीद सात दिन बाद ही अटक गई है। जिससे समर्थन मूल्य पर माल लेकर पहुंचे किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। क्रय विक्रय सहकारी समिति फलोदी की ओर से यह खरीद की जा रही है, लेकिन बारदाना नहीं होने का हवाला देकर खरीद को रोक दिया गया। जिससे सौ से अधिक किसान मंडी के बाहर तो 50 के करीब किसान मंडी के भीतर समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद का इंतजार करते रहे। मार्केटिंग के मुख्य प्रबंधक चन्द्रवीरसिंह ने बताया कि बारदाना नहीं होने और राजफेड की ओर से हेण्डलिंग चार्ज व अन्य खर्च के भुगतान का निर्धारण नहीं करने व खरीदे गए माल का भुगतान नहीं मिलने से आगे का माल खरीदना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने किसानों को बारदाना आने के बाद माल लेकर आने की अपील की है। जबकि मंगलवार को दिनभर किसान मूंगफली को समर्थन मूल्य पर तुलाई करवाने को लेकर इंतजार करते रहे। जिससे मंडी के बाहर खासी भीड़ रही और वाहनों के रोड के दोनों ओर खड़े होने से जाम के हालात भी बने। जिससे आमजन को परेशान होना पड़ा।

सहकारी बैंक में वित्तीय अनियमितता को बर्दाश्त नही किया जाएगा - सहकारिता मंत्री

- सहकारिता मंत्री ने कहा कि धारा 55 की जांच एवं कार्रवाई को समय पर करे
- सहकार से समृद्धि के 54 नवाचारों द्वारा समितियों को सुदृढ़ करे
- अधिक से अधिक नए लोगों को ब्याज मुक्त फसली ऋण देने के निर्देश दिए
- ऋण वितरण में सिबिल चेक का उपयोग किया जाए

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दक ने कहा कि बैंकों में वित्तीय अनियमितताओं पर सीधे निलंबन से बर्खास्तगी की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता लोगों की सेवा से जुड़ी हुई है। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी नियमों के के अनुसार ही कार्य करे। श्री दक अपेक्स बैक में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अनियमित ऋण वितरण के संबंध में लंबित जांचों को शीघ्र पूरा करने एवं संबंधित के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गलत ऋण वितरण पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने विशेष जोर देकर कहा कि बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु ठोस कदम उठाए एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होने पर उसकी व्यवस्था करे। उन्होंने गोदाम निर्माण में अनियमितता को लेकर कहा कि इस पर व्यय होने वाली राशि एवं निर्माण का मैकेनिज्म तैयार किया जाए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि धारा 55 की जांच एवं कार्रवाई को समय पर करे। ऋण वितरण में सिबिल चेक का उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रानुसार आवश्यकता एवं विशेष उत्पादन के आधार पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवसाय में विविधता को गति देकर सहकार से समृद्धि के 54 नवाचारों को लागू किया जाए ताकि लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। उन्होंने पैक्स कम्प्यूटराईजेशन की गति बढ़ाने एवं गो लाइव में शीघ्रता लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिक से अधिक नए लोगों को ब्याज मुक्त फसली ऋण देने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सहकारी समितियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए ताकि पारदर्शिता के साथ लोगों को वास्तविक लाभ मिल सके। बैठक में 100 दिवसीय कार्ययोजना अल्पकालीन फसली ऋण वितरण, आजीविका ऋण योजना, खेत पर आवास ऋण योजना, पैक्स द्वारा कॉमन सर्विस सेन्टर, कृषि निवेश एवं अकृषि निवेश मद में ऋण वितरण, केन्द्रीय सहकारी बैकों की अमानत सुधार, जनऔषधि केन्द्रों सहित अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की। शासन सचिव सहकारिता, श्रीमती शुचि त्यागी ने ऋण वितरण एवं क्लेम की स्थिति के बारे में बैंक अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने आरबीआई एवं नाबार्ड के मापदंडो की पालना के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनऔषधि केन्द्रों का ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर विस्तार किया जाए। उन्होंने कार्य निष्पादन रिपोर्ट की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकिंग कार्यो एवं पैक्स कम्प्यूटराईजेशन में आ रही समस्याओं एवं समाधान के बारे में विस्तार से चर्चा की एवं उचित निर्देश दिए। बैठक में रजिस्ट्रार सहकारिता, श्रीमती अर्चना सिंह ने बैंक अमानतों, सीएससी ट्राजेक्शन बढ़ाने पैक्स एज एमएससी एवं खेत पर आवास ऋण योजना पर उचित निर्देश दिए। प्रबंध निदेशक अपक्स बैंक, श्री भोमाराम ने बैठक में बिन्दुवार एजेंडा रखा। इस अवसर पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार बैंकिंग श्रीमती गुंजन चैबे सहित सहकारिता विभाग एवं अपेक्स बैंक के अधिकारी उपस्थित थे।

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक प्रकाश वैष्णव द्वारा वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स, वैष्णव फार्म परावा 343041 जिला-सांचौर (राज.) से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।